सेमीकंडक्टर उद्योग को लगेंगे पंख

प्रधानमंत्री का सिंगापुर दौरा : दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के लिए समझौता

शुभायन चक्रवर्ती

देश के सेमीकंडक्टर उद्योग का अब तेजी से विकास होगा। यहां फैलते सेमीकंडक्टर उद्योग को सहयोग देने के मकसद से भारत और सिंगापुर के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय समझौता हुआ। इसी के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़ी सिंगापुर की कंपनियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे खुल जाएंगे।

अपनी दो दिवसीय यात्रा पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के साथ-साथ वहां के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों और उद्यमियों से वार्ताएं कीं। दोनों देश संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने और मजबूत करने पर सहमत हुए। दोनों देश अगले साल राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाएंगे।

प्रधानमंत्री के रूप में अपनी 5वीं यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे मोदी ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल सहयोग, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यह साझेदारी ऐसे समय में अमल में आई है जब सेमीकंडक्टर पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्नत विनिर्माण क्षेत्र को द्विपक्षीय सहयोग के एक स्तंभ के रूप में जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने सेमीकंडक्टर फैक्टरी एईएम होल्डिंग लिमिटेड का दौरा किया, जहां उन्होंने सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

सिंगापुर सरकार ने अपने बयान में कहा, 'भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण में वैश्विक ताकत बनना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक वाहन और विनिर्माण क्षेत्र में उसकी घरेलू मांग बहुत मजबूत है। सेमीकंडक्टर उद्योग की वृद्धि से इसे बहुत अधिक फायदा होगा। सिंगापुर के स्थापित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र से इस क्षेत्र में स्थानीय कारोबारियों का रुझान तेजी से बढ़ा है, जो भारतीय बाजारों की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं।'

लंबे समय से ताइवान चिप विनिर्माण में अग्रणी बना हुआ है, इसी प्रकार सिंगापुर इलेक्ट्रिक कारों और स्मार्टफोन के लिए छोटी चिप बनाने में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। सिंगापुर सरकार के मुताबिक देश की जीडीपी में सेमीकंडक्टर उद्योग की हिस्सेदारी 7-8 प्रतिशत है। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 10 प्रतिशत मांग को पूरा करता है। इससे पहले, इसी सप्ताह कैबिनेट ने भारत में पांचवीं सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी थी। इस यूनिट की स्थापना पर 3,307 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जो प्रति दिन 60 लाख चिप का उत्पादन करेगी।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो-पीटीआई

भारत और सिंगापुर के बीच कई करार

- मोदी ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर, डिजिटल सहयोग, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर
- सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़ी सिंगापुर की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे खुलेंगे
- दोनों देश संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने और मजबूत करने पर सहमत हुए
- सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता, शिक्षा, एआई, फिनटेक, नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा

व्यापक रणनीतिक साझेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने गुरुवार को गहन बातचीत की और दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का दायरा 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाते हुए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग सहित चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मोदी ने कहा कि सिंगापुर न केवल एक साझेदार राष्ट्र है, बल्कि यह प्रत्येक विकासशील देश के लिए प्रेरणा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि 4जी (चौथी पीढ़ी के नेताओं) के नेतृत्व में सिंगापुर और भी तेजी से प्रगति करेगा। हम भारत में भी कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। कौशल विकास, डिजिटलीकरण, गतिशीलता, उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई), स्वास्थ्य सेवा, स्थिरता और साइबर सुरक्षा में दोनों देशों के बीच साझेदारी इस तंत्र की पहचान बन गई है। हम सिंगापुर-भारत रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाकर एक 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' में बदल रहे हैं।' दोनों नेताओं ने सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता, शिक्षा, एआई, फिनटेक, नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान साझेदारी के क्षेत्रों में मौजूदा सहयोग की भी समीक्षा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए संपर्क सुविधा को मजबूत करने का आह्वान किया। मोदी और वोंग ने 'हरित गलियारा' परियोजनाओं में तेजी लाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्ते इन संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। उन्होंने घोषणा की कि भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोला जाएगा। नेताओं ने भारत-आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन) संबंधों और हिंद-प्रशांत के लिए भारत के दृष्टिकोण सहित आपसी हित के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

विमानन क्षेत्र में निवेश का आह्वान

प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के कारोबारी दिग्गजों से भारतीय विमानन क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए गुरुवार को कहा कि बढ़ते घरेलू हवाई यातायात को देखते हुए भारत में 100 से अधिक नए हवाई अड्डों और अधिक विमानन कंपनियों की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि कौशल विकास से लेकर रक्षा क्षेत्र तक सहयोग में तेजी आई है और 'सिंगापुर एयरलाइंस' और 'एयर इंडिया' के बीच समझौते से संपर्क सुविधा मजबूत हुई है।

मोदी ने सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान यहां कई दिग्गज कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठक के दौरान उन्हें विमानन के अलावा ऊर्जा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के कारोबारी दिग्गजों के साथ गोलमेज बैठक में कहा कि भारत के विमानन क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं।

उन्होंने निवेश कोष, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, ऊर्जा, टिकाऊ विकास और लॉजिस्टिक क्षेत्रों की कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से कहा कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है।

(साथ में एजेंसियां)

त्योहारी सीजन के लिए तैयार कंपनियां, होंगी बंपर भर्तियां

पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी उछाल की संभावना

राघव अग्रवाल

तमाम कंपनियां त्योहारी सीजन की तैयारी में जुट गई हैं। ग्राहकों की मांग को समय पर पूरा करने के लिए वे हर साल अतिरिक्त कर्मियों की भर्तियां करती हैं। इस बार भी यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। हायरिंग प्लेटफॉर्म इनडीड ने गुरुवार को बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार मौसमी भर्तियों में 20 फीसदी उछाल आने की संभावना है। मौसमी नौकरियां अल्पकालिक होती हैं, जिनमें आमतौर पर साल के कुछ महीनों के लिए लोगों को काम पर रखा जाता है। ये अमूमन छह महीने या उससे कम अवधि के लिए ही होती हैं।

इनडीड की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई, बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में नियुक्तियां संभवतः 18 से 20 फीसदी बढ़ जाएंगी, मगर जयपुर, कोच्चि, विशाखापत्तनम, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे मझोले और छोटे शहरों में इन नौकरियों की 22 से 25 फीसदी ज्यादा मांग हो सकती है।

इनडीड ने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है, क्योंकि मझोले और छोटे शहरों में ग्राहकों की खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है। इन शहरों में अब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और उनकी खर्च योग्य आय बढ़ रही है। इसने कहा, 'इसके अलावा, इन इलाकों में इंटरनेट के प्रसार और डिजिटलीकरण से ई-कॉमर्स, खुदरा और लॉजिस्टिक्स कंपनियों का ग्राहक दायरा बढ़ा है।' इससे यह पता चलता है कि ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म त्योहारी सीजन में अब छोटे शहरों पर खूब ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मालूम हो कि भारत में त्योहारी सीजन ओणम से शुरू होकर दीवाली तक चलता है। इसमें नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे बड़े त्योहार शामिल हैं।

जेप्टो ने अहमदाबाद और कानपुर जैसे छोटे शहरों में अपना डार्क स्टोर पेश करने की घोषणा की है। जोमैटो के ब्लिंकइट ने भी कोच्चि, हरिद्वार और विजयवाड़ा जैसे मझोले शहरों में इसे पेश किया है। स्विगी इंस्टामार्ट भी अपनी कार्यक्षमता सुधारने पर काम कर रही है।

नियुक्ति एवं भर्ती सेवा प्लेटफॉर्म टीमलीज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार त्योहारी सीजन में ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी बिक्री में 35 फीसदी इजाफा होने की उम्मीद है। इनडीड के निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि इस वर्ष सबसे ज्यादा नौकरियां ई-कॉमर्स क्षेत्र में निकल रही हैं, जहां साल 2023 के मुकाबले 35 फीसदी की उछाल देखी जा रही है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स में 15 और रिटेल की भर्तियों में 14 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई है। क्विक कॉमर्स में इस वर्ष नौकरियों में 11 फीसदी का इजाफा हुआ है। पदों के लिहाज से डिलिवरी एक्जीक्यूटिव की मांग में सबसे ज्यादा 30 फीसदी की वृद्धि हुई है। उसके बाद 25 फीसदी के साथ वेयरहाउस वर्कर्स और 20 फीसदी के साथ लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर का स्थान है।

इनडीड इंडिया में सेल्स प्रमुख शशि कुमार ने कहा, 'त्योहारी सीजन देशभर में तमाम कारोबारों के लिए महत्त्वपूर्ण होता है। हम मौसमी नौकरियों के लिए नियुक्तियों में भारी वृद्धि देख रहे हैं, क्योंकि कंपनियां बढ़ती उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।' उन्होंने कहा, 'ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, क्विक कॉमर्स उद्योग इसलिए भी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि वे आज के उपभोक्ताओं की जरूरत और व्यवहार के अनुरूप काम कर रहे हैं। भारत के नौकरी बाजार का भविष्य भी यहीं हो सकता है।'

नौकरियों की बहार

- मुंबई, बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में नियुक्तियां संभवतः 18 से 20 फीसदी तक बढ़ जाएंगी
- जयपुर, कोच्चि, विशाखापत्तनम, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे मझोले और छोटे शहरों में 22 से 25 फीसदी बढ़ेगी कर्मियों की मांग

महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगें प्रधानमंत्री: राहुल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना के लिए बल्कि नोटबंदी, किसान विरोधी विधेयकों और जीएसटी के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। गांधी ने कहा कि मोदी को 17वीं सदी के महान योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के उस अपमान के लिए महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक से माफी मांगनी चाहिए, जब 26 अगस्त को राजकोट किले में उनकी प्रतिमा ढह गई थी। कांग्रेस नेता पार्टी के दिवंगत नेता पतंगराव कदम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सांगली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हालांकि शिवसेना (उद्धव) के प्रमुख उद्धव ठाकरे जनसभा में शामिल नहीं हुए। **भाषा**

केजरीवाल मामले में फैसला सुरक्षित

उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति 'घोटाले' में जमानत के अनुरोध और सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत से इनकार किए जाने और सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। सीबीआई ने अदालत से कहा कि उन्हें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए पहले निचली अदालत जाना चाहिए था। **भाषा**

ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण में उप्र आगे

संकेत कौल

सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। देशभर में पिछले दो वर्ष में नैशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) के तहत स्कैन और शेयर सेवा के जरिए बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) के लिए करीब 4.7 करोड़ ऑनलाइन पंजीकरण किए गए। इनमें 1.24 करोड़ ओपीडी टोकन अकेले उत्तर प्रदेश से जारी किए गए। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में इस सेवा के माध्यम से 10,000 से भी कम ओपीडी पंजीकरण टोकन दिए गए।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के डैशबोर्ड के 5 सितंबर तक प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण में उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश का नंबर है, जहां 81 लाख मरीजों ने ओपीडी में इलाज के लिए ऑनलाइन टोकन लिया। कुल 57 लाख टोकन के साथ बिहार तीसरे स्थान पर है। खास यह कि इस सूची में महज 949 टोकन के साथ तमिलनाडु सबसे नीचे है। हिमाचल प्रदेश नीचे से दूसरे स्थान पर है, जहां केवल 1,365 ओपीडी पंजीकरण ऑनलाइन किए गए। इसके बाद गोवा में महज 2,381 और केरल में 7,983 मरीजों ने ओपीडी में इलाज के लिए ऑनलाइन पंजीकरण टोकन लिया।

देशभर में सबसे ज्यादा ओपीडी पंजीकरण वाले 25 अस्पतालों में 15 उत्तर प्रदेश और उसके बाद पांच आंध्र प्रदेश के हैं। ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण में एम्स नई दिल्ली पहले स्थान पर है।

BSmart
Case Study Challenge

Calling all future leaders!
Dive into a real-world business challenge and stand a chance to win big.

Case Study
Ola Electric: Foretell the future
Ola Electric: IPO success, 4th largest EV claim, and debatable e-bike pricing. Let's decode Ola Electric's future game plan!

To download the app, visit rebrand.ly/BSmartChallenge or scan the QR code
Follow us on bit.ly/bsmartchannel

Rewards
1st Prize ₹5,000
2nd Prize ₹3,000
3rd Prize ₹2,000
• Top 3 winners to be featured on BSmart Platform
• Certificate to all eligible participants

Timeline
September 01 | Launch
September 15 | Submission Deadline
September 30 | Result Declaration
October 07 | Prize Money Disbursement

Terms and Conditions applied

Business Standard 50 Years of Insight

businessstandard | bsindia | business.standard | business-standard.com

सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
विज्ञापन संख्या 04/ 2024-25
संविदात्मक (पूर्णकालिक) आधार पर मुख्य अर्थशास्त्री की नियुक्ति:-2024-25

सिडबी, एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रधान वित्तीय संस्थान, पूर्णकालिक संविदा आधार पर निम्नलिखित पद के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

क्रम सं	पद	पद कूट	कुल रिक्तियां	आरक्षित रिक्तियाँ					
				अना	ईडब्ल्यूएस	अपिव	अजा	अजजा	पीडब्ल्यूबीडी (वीआई)
1	मुख्य अर्थशास्त्री	01	01	01	–	–	–	–	01*

पूर्ण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **26 सितम्बर, 2024** है। विस्तृत विज्ञापन जिसमें पात्रता मानदंड, पारिश्रमिक, चयन प्रक्रिया आदि और आवेदन पत्र शामिल हैं, सिडबी की वेबसाइट **www.sidbi.in** पर उपलब्ध हैं। कोई भी संशोधन सिडबी की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

* अधिक जानकारी के लिए कृपया विस्तृत विज्ञापन देखें।

www.bankofbaroda.in
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बड़ौदा सन टॉवर, मुंबई
निविदा सूचना
बैंक ऑफ़ बड़ौदा निम्नलिखित के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है:

क्रम सं.	निविदा का नाम	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1	5 साल की वारंटी के साथ हार्डवेयर सुरक्षा मॉड्यूल 'थेल्स पेशील्ड 10K' की आपूर्ति, क्रियान्वयन और रखरखाव के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध	27 सितंबर, 2024
2	बैंक ऑफ़ बड़ौदा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए मौजूदा नेटऐप स्टोरेज को बढ़ाने हेतु एसएसडी की आपूर्ति, इन्स्टॉलेशन और रखरखाव के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध	27 सितंबर, 2024

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड तथा सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध है।
'अन्य सूचना', यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट पर **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड तथा ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर जारी किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें।
स्थान: मुंबई
दिनांक: 06.09.2024
मुख्य महाप्रबंधक (आईटी)
67/24-25

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India
बीओ : रोहिणी सेक्टर-24 शाखा
फोन : 011 27934699 एंव 27934199

सरफासी ऐक्ट
अनुलग्नक "क"
(कर्जदार(रों) को, जिसके/जिनके द्वारा अपनी किसी/किन्हीं आस्ति(यों)/सम्पत्ति(यों) पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है। इस सूचना की प्रति उस/उन गारंटर(रों) को पृष्ठांकित की जानी है, जिसके/जिनके द्वारा अपनी किसी/किन्हीं आस्ति(यों)/सम्पत्ति(यों) पर प्रतिभूति हित सृजित नहीं किया गया है)
सेवा में,
श्री जय शंकर प्रसाद महतो (आवेदक)
श्रीमती ममता (सह-आवेदक), मकान नंबर 146, द्वितीय तल, पाकेट-13, सेक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली, नई दिल्ली
श्रीमान्,
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना
बैंक ने, आपके द्वारा किए गए अनुरोध पर, आपको कुल राशि रू. 24,00,000/- की विभिन्न क्रेडिट सुविधाएं मंजूर की थी। हम हमारे द्वारा मंजूर की गई विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं और इस सूचना की तिथि तक उनके तहत बकाया राशि का विवरण यहां नीचे दे रहे हैं :-

सुविधा का प्रकार	स्वीकृत सीमा (लिमिट)	बकाया राशि
(क) आवास ऋण	रू. 24,00,000/-	रू. 21,11,215.63/-

2. बैंक द्वारा मंजूर की गई उपरोक्त क्रेडिट सुविधाएं निम्नलिखित आस्तियों/प्रतिभूतियों द्वारा प्रत्याभूत है (बैंक को प्रभारित सम्पत्तियों/आस्तियों का विवरण) :-
(क) मकान नंबर 146, द्वितीय तल, पाकेट-13, सेक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली-110085
(ख)
3. चूंकि आपने उक्त क्रेडिट सुविधाओं के तहत बैंक की आपकी तरफ बकाया राशि चुकाने में चूक की है, हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आपका खाता दिनांक 29-07-2024 की प्रभावी तिथि से अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है।
4. उपरोक्त कारणों के दृष्टिगत, हम एतद्द्वारा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना देते हैं और आपसे आपकी तरफ बैंक की बकाया पूर्ण राशि रू. 21,11,215.63/-(सूचना की तिथि तक संविदात्मक बकाया) का भुगतान आगे उस पर मासिक अंतरालों पर चक्रवृद्धि के साथ 9.45 प्रतिशत की दर पर ब्याज तथा आपके द्वारा भुगतान किए जाने तक बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों सहित, इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग करते हैं, जिसमें असफल रहने पर कृपया नोट करें कि हम बैंक को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग, उपरिवर्णित प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध, पूर्ण रूप से आपकी जोखिम व लागत पर करेंगे।
5. जबकि हम आपसे बैंक की पूरी बकाया राशि आपके द्वारा भुगतान किए जाने तक बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों सहित चुकाने और प्रत्याभूत आस्तियां उपरिवर्णित अवधि के भीतर छुड़ाने की मांग करते हैं, कृपया विशेष ध्यान दें कि सरफासी ऐक्ट की धारा 13(8) के तहत आपको प्रत्याभूत आस्तियां छुड़ाने का अधिकार यह सूचना प्रकाशित होने की तिथि तक अथवा आम जनता से कोटेशन या निविदा आमंत्रित करने अथवा पट्टा, समनुदेशन द्वारा अंतरण हेतु गुप्त समझौते अथवा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की तिथि तक ही होगा।
6. उपरिवर्णित शक्तियों का प्रयोग करने से प्राप्त राशि का उपयोग सर्वप्रथम हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों के भुगतान में किया जाएगा और उसके बाद बैंक की उपरिवर्णित बकाया राशि, इस सूचना की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक संविदात्मक ब्याज सहित चुकता करने हेतु किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई होगी, बैंक की कुल बकाया राशि (कर्जदार या गारंटर के रूप में बैंक को देय किसी अन्य राशि सहित) की पूरी वसूली के बाद, आपको सौंप दी जाएगी।
7. यदि उक्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा प्राप्त राशि से बकाया राशि की पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो हमारा आपके तथा आपकी अन्य आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित है, जिसमें बकाया राशि की वसूली सभी लागतों सहित करने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण/न्यायालय में कानूनी/वसूली कार्यवाही प्रस्तुत करने का अधिकार शामिल है।
8. कृपया नोट करें कि उपरोक्त अधिनियम की उप-धारा (13) के तहत, यह सूचना प्राप्त होने के बाद, आप उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियां अंतरित नही कर सकते हैं अथवा बिक्री, पट्टा, लाइसेन्स, उपहार, बंधक या अन्य किसी प्रकार से कोई ऋणभार सृजित नहीं कर सकते हैं।
9. अधोहस्ताक्षरी यह सूचना जारी करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने हेतु बैंक का सम्यक् प्राधिकृत अधिकारी है।
10. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, कि आपको यह सूचना, बैंक को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार अथवा उपाय को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना जारी की जा रही है।
तिथि : 19-08-2024, स्थान : दिल्ली **बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी**